आज

पटना, शुक्रवार, २१ जनवरी, २०११ ५

अगले वित्तीय में वेंडरों के लिए लागू होगी नीति

(आज समाचार सेवा)

पटना। नगर विकास एवं आवास मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि नये वित्तीय वर्ष में वेंडरों के लिए नयी नीति लागू की जायेगी। नीति के तहत वेंडरों को निबंधित किया जायेगा ताकि उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। श्री कुमार गुरुवार को श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया (नासवी), निदान तथा सेंटर फॉर सिविल सोसायटी द्वारा वेंडर दिवस पर आयोजित राज्यस्तरीय फुटपाथ दुकानदार सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि निबंधित वेंडरों को पहचान पत्र दिया जायेगा, जिसके आधार पर उनको सरकार से वित्तीय सहायता भी मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि वेंडरों के कल्याण के लिए स्वास्थ्य बीमा की शुरुआत की जायेगी, ताकि बीमार पड़ने पर उनका मुफ्त इलाज हो सके। जल्द हीं उनके लिए स्वास्थ्य शिविर भी लगाया जायेगा। इस शिविर में उनके स्वास्थ्य की मुफ्त जांच कर निःशुल्क दवाएं उपलब्ध करायी जायेंगी। श्रम संसाधन मंत्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल ने समारोह में वेंडरों के श्रम अधिकारों की रक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा की गारंटी का वायदा किया। नासवी के राष्ट्रीय

संयोजक अरविन्द सिंह ने कहा कि हमारे सब्र का बांध टूट रहा है। हम सरकार के आश्वासन को सुनते-सुनते थक चुके हैं। उन्होंने के प्रदेश के वेंडर रोजी-रोटी, सम्मान व सुरक्षा की खातिर निर्णायक लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। राष्ट्रीय समन्वयक रंजीत अभिज्ञान ने पांच सूत्री प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में उन्होंने २००४ में बनी राष्ट्रीय फेरी नीति पर गंभीरतापूर्वक अमल करने व शीघ्र कानून बनाने, सड़क किनारे का २.५ मीटर भाग वेंडरों के लिए छोड़ने, शिकायत निवारण तंत्र बनाने तथा वेंडिंग कमेटियों में वेंडरों को उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग की। इस मौके पर ट्रेड यूनियन नेता चंद्रप्रकाश सिंह, निदान के कार्यक्रम प्रबंधक राकेश त्रिपाठी व संजय कुमार भी मौजूद रहे।

डीएम ने की बाल विकास परियोजना के कार्यों की समीक्षा

पटना। जिलाधिकारी जितेन्द्र कुमार सिन्हा ने गुरुवार को बाल विकास परियोजना पटना सदर-१ के कार्यालय में आंगनबाड़ी सेविकाओं के कार्यों की समीक्षा की तथा उनकी गुणवत्ता में सुधार लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इन कार्यों का संपादन सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरुप किया जाए ताकि लाभान्वितों को उसका समुचित लाभ मिल सके। इस मौके पर संबंधित सीडीपीओ शबाना कशफी भी मौजूद रहीं। गौरतलब है कि पटना सदर-१ परियोजना में कुल १२८ केन्द्र हैं, जिसमें १२० सेविका कार्यरत हैं।